

सिविल सेवा दिवस - 2018 Civil Services Day - 2018

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार

Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration

(Awardees' Citation)



Department of Administrative Reforms & Public Grievances
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Government of India





सिविल सेवा दिवस - 2018 Civil Services Day - 2018

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार

Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration

(Awardees' Citation)



Department of Administrative Reforms & Public Grievances
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Government of India



सिविल सेवा दिवस - 2018

लोक प्रशासन उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार



Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration

विषय-सूची

प्राथ	मिकता कार्यक्रमों में	पुरस्कार	पृ.सं.		
1.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना				
	समूह	जिला/कार्यान्वयन इकाई			
(ক)	पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य	पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा	2		
(ख)	अन्य राज्य	बीड, महाराष्ट्र	4		
2.	डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन				
(ক)	पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य	बिष्णुपुर, मणिपुर	8		
(ख)	केंद्र शासित प्रदेश	दमन, दमन और दीव	10		
(য	अन्य राज्य	सोनीपत, हरियाणा	12		
3.	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण	r)			
(ক)	पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य	कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	16		
(ख)	अन्य राज्य	नीमच, मध्य प्रदेश	17		
4.	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)				
(ক)	केंद्र शासित प्रदेश	पुडुचेरी, शहरी स्थानीय निकाय, पुडुचेरी	18		
(ख)	अन्य राज्य	ग्रेटर हैदराबाद महानगर निगम, तेलंगाना	19		
5.	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना				
(ক)	पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य	धेमाजी, असम	22		
(ख)	अन्य राज्य	करीमनगर, तेलंगाना	24		
6.	नवाचार में पुरस्कार				
क्र.सं.	पहल का नाम	संगठन			
1.	उन्नयन बांका-प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए शिक्षा में बदलाव	जिला प्रशासन, बांका, बिहार	27		
2.	जीएसटी – एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार	टीम जीएसटी – राजस्व विभाग, भारत सरकार	29		
7.	नवाचार (अपर सचिव/संयुक्त सचिव तथा निदेशक/उप सचिव श्रेणी)				
1.	भारत में व्यापार की सुगमता	टीम इंडिया – श्री शैलेन्द्र सिंह, अपर सचिव तथा श्री रविन्द्र, संयुक्त सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), भारत सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व	31		
2.	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) – सूचना, शिक्षा व संचार	श्री युगल किशोर जोशी, निदेशक, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार	33		

Contents

Awards in the Priority Programmes					
1	Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana				
	Group	District / Implementing Unit			
(a)	NE & Hill States	West Tripura, Tripura	2		
(b)	Other States	Beed, Maharashtra	4		
2	Promoting Digital Payments				
(a)	NE & Hill States	Bishnupur, Manipur	8		
(b)	Union Territories	Daman, Daman & Diu	10		
(c)	Other States	Sonipat, Haryana	12		
3	Pradhan Mantri Awas Yoja	na (Gramin)			
(a)	NE & Hill States	Kangra, Himachal Pradesh	16		
(b)	Other States	Neemuch, Madhya Pradesh	17		
4	Pradhan Mantri Awas Yoja	nna (Urban)			
(a)	Union Territories	Puducherry ULB, Puducherry	18		
(b)	Other States	Greater Hyderabad Municipal Corporation, Telangana	19		
5	Deen Dayal Upadhyaya Gr	ameen Kaushalya Yojana			
(a)	NE & Hill States	Dhemaji, Assam	22		
(b)	Other States	Karimnagar, Telangana	24		
6	Awards in Innovation				
SI. No.	Name of the Initiative	Organization			
1.	Unnayan Banka- Reinventing Education using Technology	District Administration Banka, Bihar	27		
2.	GST-One Nation, One Tax, One Market	Team GST, Department of Revenue, Gol	29		
7	Innovation (AS/JS & Dir/DS Category)				
1.	Ease of Doing Business in India	Team India represented by Sh. Shailendra Singh, Additional Secretary & Sh. Ravinder, Joint Secretary, DIPP, Gol	31		
2.	Information, Education and Communication of Swachh Bharat Mission (Gramin)	Sh. Yugal Kishore Joshi, Director, Ministry of Drinking Water & Sanitation, Gol	33		

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सिविल सेवा दिवस - 2018

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Civil Services Day - 2018

योजना का सार : पीएमएफबीवाई

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) फसल बीमा स्कीम है जिसमें देश के किसानों के लिए सफल बीमा सहायता की परिकल्पना की गई है।

पीएमएफबीवाई का उद्देश्य

- आकस्मिक घटनाओं से हुए फसल के नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना,
- खेती में अपनी निरन्तरता सुरक्षित करने के लिए किसानों की आय स्थिर करना,
- किसानों को नवाचार और आधुनिक कृषि प्रयोग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना
- कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करते हुए कृषि क्षेत्र में उत्पादन बनाए रखने में सहायता करना है।

प्राथमिकता कार्यक्रम किसानों को उत्पादन के जोखिमों से बचाने के अतिरिक्त, खाद्य सुरक्षा, फसल-विविधता और पैदावार बढ़ाने और कृषि क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में योगदान करता है।

Brief of the Scheme: PMFBY

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) is a crop insurance scheme which envisages an efficient insurance support for farmers of the country.

PMFBY aims at supporting sustainable production in agriculture sector by:

- Providing financial support to farmers suffering crop loss/damage arising out of unforeseen events
- Stabilizing the income of farmers to ensure their continuance in farming
- Encouraging farmers to adopt innovative and modern agricultural practices
- Ensuring flow of credit to the agriculture sector

The priority programme contributes to food security, crop diversification and enhancing growth and competitiveness of agriculture sector besides protecting farmers from production risks.

पुरस्कृत जिला – पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा समूह – पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य

इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में किया गया अनुकरणीय कार्य

- जिला, ब्लॉक, सैक्टर और ग्राम पंचायत स्तरों पर 2016-17 में 109 और 2017-18 में 140 प्रचार अभियान और कृषक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- सोशल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व एम-किसान स्टेट पोर्टल के माध्यम से प्रचार किया गया।
- जिला प्रशासन द्वारा नए बीमित कृषकों को प्रोत्साहन देने के लिए सघन जागरुकता अभियानों के साथ सभी स्टेकहोल्डरों के साथ नियमित समन्वयन और समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।
- कृषकों की अधिक सहभागिता के लिए सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर ग्रामस्तरीय उद्यम (वीएलई) संचालित किए गए। स्व-सहायता समूह, कृषक क्लब ने कार्यक्रम के प्रति जागरुकता का प्रसार किया।
- फसल क्षति के निर्धारण और आवेदनों की प्रक्रिया के दौरान ग्राम स्तर के कार्यकर्ता (वीएलडब्ल्यू)
 और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि दोनों उपिश्यित थे।
- विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर बीमित कृषकों से संबंधित जानकारी समय
 पर अपलोड की गई थी।
- फसल कटाई के प्रयोगों (सीसीई) के दौरान जियो टैगिंग और फोटो अपलोड किए गए। सीसीई के इलेक्ट्रॉनिक सब्मिशन के अंतर्गत 2016 की खरीफ के लिए 63.2% और 2016 की रबी के लिए 61.4% का लक्ष्य प्राप्त किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, क्षितपूर्ति की राशि का इलेक्ट्रॉनिक अंतरण सीधे किसानों के बैंक खातों में कराया गया।

Awarded District – West Tripura, Tripura Group – North East & Hill States

Exemplary Work Done in District under the Programme

- 109 publicity campaigns and farmers' awareness programmes have been conducted in 2016-17, and 140 have been conducted in 2017-18 at the District, Block, Sector, and Gram Panchayat levels.
 Publicity has been done through social and electronic media and m-Kisan State Portal.
- Regular co-ordination and review meetings with all stakeholders were conducted along with intensive awareness campaigns by District Administration to incentivise newly insured farmers.
- Village Level Entrepreneurs (VLEs) operated at Common Service Centres (CSCs) for the increased participation of farmers. SHGs, Farmer's Club spread awareness about the Programme.
- Both Village Level Workers (VLW) and Insurance Company representatives were present during the processing of applications and assessment of crop damage.
- Information regarding insured farmers was uploaded timely on Crop Insurance Portal by various financial institutions.
- Geo-tagging and photo uploading during Crop Cutting Experiments (CCE) were also done. Under electronic submission of CCE, 63.2% of the target has been achieved for Kharif 2016 and 61.4% for Rabi 2016.
- Additionally, electronic transfer of compensation directly into bank accounts of farmers took place.

प्रभाव वर्ष २०१६-१७ में प्रस्तुत किए गए सभी ४८ दावे निपटा दिए गए थे।

	पैरामीटर	खरीफ		रबी	
		2016	2017	2016	2017
1.	बीमित किसानों के आवेदनों की कुल संख्या	279	358	1,659	4,311
2.	गैर-ऋणी किसानों के आवेदनों की प्रतिशतता	26.5%	34.4%	70.8%	92.1%
3.	कुल फसली क्षेत्र (हेक्टेयर)	59,948			
4.	बीमित फसली क्षेत्र की प्रतिशतता	0.2%	0.3%	0.7%	1.1%

ImpactAll 48 submitted claims were settled in the year 2016-17.

	Parameters	Kharif		Rabi	
		2016	2017	2016	2017
1.	Total number of insured farmer applications	279	358	1,659	4,311
2.	Percentage of insured non-loanee farmer applications	26.5%	34.4%	70.8%	92.1%
3.	Total cropped area (hectares)	59,948			
4.	Percentage of insured cropped area	0.2%	0.3%	0.7%	1.1%

पुरस्कृत जिला – बीड, महाराष्ट्र समूह – अन्य राज्य

इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में किया गया अनुकरणीय कार्य

- जिला प्रशासन ने लोगों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के बारे में शिक्षित करने के लिए सभी 1031 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया।
- ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए 2,949 सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) स्थापित किए गए।
- जिलास्तरीय कॉल सेंटर, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे आकाशवाणी, स्थानीय केबल चैनलों,
 प्रकाशित बुलेटिनों और पोस्टरों का उपयोग किया गया।
- सीएससी केंद्रों के जरिए फसल बीमा कराने के लिए ग्राम स्तर पर आरडीडी, राजस्व स्टाफ तथा वीएलई को प्रशिक्षण दिया गया।
- संभागीय आयुक्त और कृषि आयुक्त जैसे विरष्ट अधिकारीगण चर्चा-समूहों में सिम्मिलित हुए।
- किसानों के लिए आवेदन-पत्र जमा कराने हेतु रिववार और सार्वजनिक अवकाश के दौरान भी बैंक खुले रखे गए और कृषि मित्रों ने आवेदन पत्र भरवाने में सहायता करते हुए सहभागिता की।
- किसान उत्पादक संगठनों, जिले के आदर्श किसानों, गत शेती किसानों आदि ने इस प्रक्रिया में सहायता की। गांवों में ग्लोबल पर्ली, मानवलोक जैसे गैर-सरकारी संगठनों और मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास मित्रों ने भी कार्यक्रम कार्यान्वयन में भाग लिया।
- आवेदन ऑनलाइन पोर्टल (http://agri-insurance.gov.in/login.aspx) के जरिए अपलोड किए गए। सीसीई परिणाम मोबाइल एप्प (सीसीई एग्री) के माध्यम से प्रस्तुत किए गए और जियो–टैग्ड फोटो का उपयोग अनिवार्य किया गया।
- इस स्कीम में आधार संख्या (डुप्लिकेशन समाप्त करने आदि) के प्रयोग से संपूर्ण आधार प्रमाणीकरण का उपयोग किया गया और उसे जन-धन खाते से जोड़ा गया। इसमें नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना, गत शेती योजना, मेगल त्याला शेत ताले और मेगल त्याला विहिर जैसी स्कीमों का भी उपयोग किया गया।

Awarded District – Beed, Maharashtra Group – Other States

Exemplary Work Done in District under the Programme

- District administration conducted special Gram Sabhas in all 1031 Gram Panchayats to educate the people about PMFBY.
- 2,949 Common Service Centres (CSC) were established providing technical assistance to Village Level Entrepreneurs (VLE).
- District level call centre, print media and electronic media was used such as All India Radio, local cable channels, published bulletins and posters.
- Training was provided to RDD & Revenue Staff at Village Level and VLE for filling of crop insurance form through CSC centers.
- Senior officers like Divisional Commissioner and Agriculture Commissioner were involved in District level discussion groups.
- Banks were opened on Sundays and public holidays for farmers to submit applications and Krishi Mitras participated by assisting in filling application forms.
- Farmers' producing organizations, ideal farmers in the District, Gat Sheti farmers, etc. assisted in the process. NGOs like Global Parli, Manavlokand Chief Minister Rural Development Fellows in villages also got involved in the programme implementation.
- Applications were uploaded online via an online portal (http://agri-insurance.gov.in/login.aspx). CCE results were submitted through mobile app (CCE Agri) and compulsory usage of geo-tagged photo took place.
- The scheme used compete Aadhaar authentication via usage of Aadhaar number (de-duplication, etc.) and linkage to Jan Dhan Account. It also leveraged other schemes like Nanaji Deshmukh Krishi Sanjivani Yojana, Gat Sheti Yojana, Magel Tyala Shet Tale and Magel Tyala Vihir.

प्रभाव

खरीफ और रबी 2016 के 100% दावों का समय पर (क्रमशः 232.84 करोड़ और 4.05 करोड़ रुपए) निपटान किया गया। यह जिला खरीफ 2016, 2017 और रबी 2016, 2017 में अधिकतम आवेदन प्राप्त करने में राज्य का पहला जिला रहा।

	पैरामीटर	खरीफ		रबी	
		2016	2017	2016	2017
1.	बीमित किसानों के आवेदनों की कुल संख्या	13,58,466	12,19,837	1,61,074	3,78,274
2.	गैर-ऋणी किसानों के आवेदनों की प्रतिशतता	84.4%	92.8%	97.8%	98.6%
3.	कुल फसली क्षेत्र (हेक्टेयर)	10,38,800			
4.	बीमित फसली क्षेत्र की प्रतिशतता	48,8%	53%	9.5%	19.7%

Impact

100% claims were settled of Kharif and Rabi 2016 within time (Rs. 232.84 crores and Rs. 4.05 crores, respectively). District was 1st in the state to get maximum number of applications in Kharif 2016, 2017 and Rabi 2016, 2017.

	Parameters	Kha	arif	Rabi		
		2016	2017	2016	2017	
1.	Total number of insured farmer applications	13,58,466	12,19,837	1,61,074	3,78,274	
2.	Percentage of insured non-loanee farmer applications	84.4%	92.8%	97.8%	98.6%	
3.	Total cropped area (hectares)	10,38,800				
4.	Percentage of insured cropped area	48.8%	53%	9.5%	19.7%	

डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन



सिविल सेवा दिवस – 2018

Promoting Digital Payments



Civil Services Day - 2018

स्कीम का सार : पीडीपी

डिजिटल भारत कार्यक्रम भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका विजन भारत को डिजिटली सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना है। 'आकृतिविहीन', कागजरिहत, नकदीरिहत' डिजिटल भारत की सुस्पष्ट भूमिकाओं में से एक है। भारत सरकार ने डिजिटल भुगतान के प्रोत्साहन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है तािक देश के सभी क्षेत्रों को डिजिटल भुगतान सेवाओं के औपचारिक दायरे में लाया जा सके। भारत के सभी नागरिकों के लिए सुविधाजनक, आसान, किफायती, तेज और सुरक्षित तरीके से निर्बाध डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है।

सरकार डिजिटल भुगतान अवसंरचना को मजबूत बनाने और सभी स्टेकहोल्डरों के साथ डिजिटल भुगतानों को प्रोत्साहन के जिए जागरुकता उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है तािक, इस देश के नागरिकों को डिजिटली सशक्त बनाने की सरकार की परिकल्पना को साकार किया जा सके। नागरिकों को डिजिटल लेन-देन करने के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और जागरुकता उत्पन्न करने के लिए सभी स्टेकहोल्डरों के सहयोग से कार्यनीतियां और दृष्टिकोण बनाने के लिए समर्पित 'डिजिधन मिशन' गटित की गई है।

Brief of the Scheme: PDP

The Digital India programme is a flagship programme of the Government of India with a vision to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy. "Faceless, Paperless, Cashless" is one of the professed roles of Digital India. Promotion of digital payments has been accorded highest priority by the Government of India to bring each and every segment of the country under the formal fold of digital payment services. The vision is to provide facility of seamless digital payment to all citizens of India in a convenient, easy, affordable, quick and secured manner.

Government is working on strengthening of digital payment infrastructure and creating awareness through promotions of digital payments with all the stakeholders to achieve Government's vision of making citizens of this country digitally empowered. Citizens have been provided multiple options to make digital transactions. A dedicated 'Digi Dhan Mission' has been setup in MeitY for building strategies and approaches in collaboration with all stakeholders to promote digital payments and create awareness.

पुरस्कृत जिला – बिष्णुपुर, मणिपुर समूह – पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य

इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में किया गया अनुकरणीय कार्य

- डिजिटल भुगतान मिशन के बारे में जागरुकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से स्थानीय लोगों सहित विभिन्न नागरिक समाज को नियमित तौर पर शामिल किया गया।
- इसके अलावा वित्तीय साक्षरता और डिजिटल भुगतान के बारे में शिक्षित करने के लिए घर-घर अभियान चलाया गया। स्कूलों और कॉलेजों में प्रतियोगिताओं के साथ कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- करांग द्वीप दूरदराज का पिछड़ा क्षेत्र था जो लंबे समय से विद्रोह की समस्या के कारण जिले से अपेक्षाकृत अलग-थलग था। इस संबंध में, डिजिटल भुगतान के लिए प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहन राशि दी गई और द्वीप को 5 पीओएस मशीनें उपलब्ध कराई गईं। द्वीप में समुदाय को जोड़ने के लिए स्व सहायता समूह (एसएचजी) तथा यूथ क्लबों को शामिल किया गया तथा आधार दर्ज कराने एवं बैंक खाता खोलने के समान्तर कार्यकलाप किए गए। इसके अलावा, खाद डीलरों के लिए पीओएस मशीनें लगाने के साथ हर दुकान पर जागरुकता उत्पन्न की गई।
- डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए बाजार में व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच अभियान चलाए गए। डिजिटल वित्तीय लेन-देन के बारे में जानकारी का प्रसार करते हुए नकदीरिहत, भ्रष्टाचार- मुक्त भारत के निर्माण में सरकार की परिकल्पना में योगदान करने के लिए 'आई प्लेज' अभियान शुरू किया गया।
- बीएचआईएम (भीम) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन स्कीम शुरू की गई (अर्थात् भीम इंस्टॉल करें और 50/– रु. पाएं), चालू खाता खोलने वाले खाद डीलरों और व्यापारियों को निःशुल्क पीओएस मशीनें उपलब्ध कराई गईं।
- डिजिटल बिष्णुपर डिजिटल भुगतान के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ऑनलाइन चैनल शुरू किया गया। इसके अलावा, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए सोशल मीडिया का भी उपयोग किया गया।

Awarded District – Bishnupur, Manipur Group – North East & Hill States

Exemplary Work Done in District under the Programme

- With the aim to create awareness about Digital Payments mission, local people were involved along with different civil societies regularly.
- Further, door-to-door campaign were organised for financial literacy and to educate people about the digital payments. Workshops were conducted along with competitions in schools and colleges.
- Karang Island was a remote and backward region which was relatively cut-off from the District due to insurgency issue for a long time. In this regard, incentives were provided for training towards digital payments and 5 POS machines were provided on the island. Self Help Groups (SHGs) and youth clubs were involved for community mobilization and parallel activities were conducted on the island for Aadhaar enrolment and bank account opening. Additionally, shop-to-shop awareness was also provided coupled with set up of POS machines for fertilizer dealers.
- Campaigns were launched in market areas among merchants and consumers to promote digital payments. An 'I Pledge' campaign was launched to contribute to the Government's vision of creating a cashless, and corruption free India by spreading information about digital financial transactions.
- Incentive scheme were provided to promote BHIM (i.e. 'Install BHIM and get INR/-50'). Free POS machines were provided for merchants and fertilizer dealers who open current account.
- Digital Bishnupur An online channel was launched to make people literate about digital payments and create awareness among the citizens. In addition, social media interventions were made for promoting digital payments.

प्रभाव

- जिले का करांग द्वीप देश का पहला नकदीरिहत द्वीप बना।
- एसबीआई बिष्णुपुर शाखा से नकदी प्रवाह में 33% तक की कमी आई तथा बिष्णुपुर जिले ने राज्य डिजिधन मेला, 2017 में चित्रकारी और स्लोगन लेखन में द्वितीय स्थान प्राप्त किया।
- सभी २४ ग्राम पंचायतें, ६ नगर निगम परिषद सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) सुविधायुक्त हैं।
- 92% बैंक खातों में मोबाइल नंबर दर्ज हैं तथा 70% बैंक खातों में आधार नम्बर दर्ज हैं।
- इसके अलावा, पिछले 20 महीनों में डिजिटल भुगतान माध्यमों से बिजली बिलों के भुगतान की प्रतिशतता 78% से बढ़ कर 97% हो गई है।

Impact

- Karang Island of the District became first cashless island of the country.
- Cash outflow per capita from SBI Bishnupur branch reduced by 33% and Bishnupur district got the 2nd position in painting and slogan writing at state "Digi-DhanMela" 2017.
- All 24 Gram Panchayats, 6 Municipal Councils are enabled with Public Financial Management System (PFMS) facility.
- 92% of Bank accounts were seeded with Mobile and 70% of Bank accounts were seeded with Aadhaar.
- Further, percentage of electricity bills paid through digital payment mode increased from 78% to 97% in the last 20 months.

पुरस्कृत जिला – दमन, दमन और दीव समूह – केंद्र शासित प्रदेश

इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में किया गया अनुकरणीय कार्य

- जिले में 'प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करें' मॉडल अपनाते हुए डिजिटल भुगतान की जागरुकता उत्पन्न की गई। विभिन्न क्षेत्रों और समूहों के लगभग 1000 लोगों को गहन प्रशिक्षण दिया गया।
- बैनरों, होर्डिगों, सामूहिक एसएमएस तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए उक्त कार्यक्रम का प्रचार किया गया।
- 700 से अधिक उद्योगपितयों के लिए विशेष बैठक आयोजित की गई जहां उन्हें नकदीरिहत भुगतान के विभिन्न तरीकों पर प्रशिक्षण दिया गया तथा यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया कि उनके कर्मचारी और कामगार भी नकदीरिहत भुगतान को अपनाएं।
- इसके अलावा, घर–घर अभियान के लिए 140 टीमें गठित की गईं (ताकि, यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक परिवार से कम से कम एक व्यक्ति डिजिटल लेने–देन करे)।
- मेगा नकदीरहित दमन अभियान शुरू किया गया जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारियों ने 3000 लोगों को डिजिटल भुगतान के संबंध में संबोधित किया। उद्योगों के लिए अनिवार्य किया गया कि वे केवल बैंक खातों के माध्यम से ही भुगतान करें।
- विद्यार्थियों, अध्यापकों और छोटे विक्रेताओं को शामिल करते हुए डिजिटल भुगतान वीडियो बनाए गए तथा उन्हें व्हाट्सएप्प, फेसबूक और ट्विटर पर प्रसारित किया गया।

Awarded District – Daman, Daman & Diu Group – Union Territories

Exemplary Work Done in District under the Programme

- Digital payments awareness was created by following 'Train the Trainers' model in the District. Around 1000 people from various sectors and groups were provided extensive training.
- Promotions were done for the programme by leveraging banners, hoardings, mass SMS and social media platforms.
- A special meeting was organized for more than 700 industrialists where they were imparted training on various modes of cashless payments and urged to ensure that their employees and workers also switch to cashless modes of payments.
- Further, 140 teams were formed to undertake door-to-door campaigns (to ensure that at least 1 person from each household does a digital transaction).
- A mega Cashless Daman campaign was launched where the District Administration officials addressed 3000 people on digital payments. It was made mandatory for industries to make payment only through bank accounts.
- Digital payments videos involving students, teachers, small vendors were made and circulated over WhatsApp, Facebook and Twitter.

प्रभाव

- सभी 1 1 पंचायतों में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के जरिए ही निधि संवितरित की गई तथा नागरिक सेवा केंद्रों पर नकदीरिहत धन संग्रहण सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।
- पीओएस मशीनें और अन्य डिजिटल भुगतान सुविधाएं सभी 38 उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध कराई गईं। सभी 10,000 मछुआरों ने केवल नकदीरहित तरीके से ही डीजल खरीदा।
- सभी उद्योगों ने अपने कामगारों को 100% नकदीरिहत भुगतान किया। सभी शराब की दुकानों,
 पेट्रोल पंपों, रेस्त्रां और होटलों में डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।
- इसके अलावा, नकदीरहित नागरिक सेवाएं (अर्थात् जी 2 सी, बी 2 सी सेवाएं) 37 सामान्य सेवा केंद्रों पर उपलब्ध कराई गईं।
- सरकार से सरकार को भुगतान 100% डिजिटल है तथा लाभार्थियों को सरकारी भुगतान पूरी तरह से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) द्वारा ही किया गया। 1000/− रु. से अधिक की सभी सरकारी प्राप्तियां डिजिटल भुगतान के जिरए ही स्वीकार की जाती हैं।
- 92% बैंक खातों में मोबाइल नम्बर दर्ज हैं तथा 83% खातों में आधार नम्बर दर्ज हैं।
- पिछले 20 महीनों में डिजिटल भुगतान मोड के जरिए बिजली बिल भुगतान की प्रतिशतता 21% से बढ़ कर 46% हो गई है।

Impact

- In all 11 Panchayats, funds were disbursed through Public Financial Management System (PFMS) only and cashless fund collection facilities were available at Citizen Services Centres.
- POS machines and other digital payment facilities were provided in all 38 Fair Price Shops. All 10,000 fishermen purchased diesel through cashless methods only.
- All industries moved to 100% cashless payment of salaries to workers. All distilleries, petrol pumps, restaurants and hotels have digital payment facilities.
- Further, Cashless Citizens Services (i.e. G2C, B2C services) were provided at 37 Common Service Centres (CSCs).
- Government to Government payments were 100% digital and Government payments to beneficiaries was 100% via Direct Benefit Transfer (DBT) only. All Government receipts above Rs. 1000 were accepted through digital payment only.
- 92% of Bank accounts were seeded with Mobile and 83% of Bank accounts were seeded with Aadhaar.
- The percentage of electricity bills paid through digital payment mode increased from 21% to 46% in the last 20 months.

पुरस्कृत जिला – सोनीपत, हरियाणा समूह – अन्य राज्य

इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में किया गया अनुकरणीय कार्य

- अधिकतम आवाजाही वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए स्टेकहोल्डरों और प्रतिष्ठानों की पहचान की गई।
- डिजिधन मेला आयोजित किया गया जिसमें 170 स्टॉल लगाए गए और लगभग 1,50,000 लोग आए तथा 112 पुरस्कार दिए गए।
- डिजिटल अवसंरचना बढ़ाने के लिए डिजि अवसंरचना की उपलब्धता और अपेक्षाओं के अंतराल की पहचान की गई।
- 1,100 मध्यम आकार के बैनर लगाए गए तथा 1,00,000 पर्चे परिचालित किए गए। इसके अलावा, जिले के सभी नगरों के ऑटोरिक्शाओं में बैनर चिपकाए गए।
- सभी सरकारी स्कूलों में प्रातःकालीन प्रार्थना सभा के दौरान विद्यार्थियों को नकदीरहित भुगतान के लाभ के बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त, निजी स्कूलों को निर्देश दिए गए कि डिजिटल भुगतान पद्धितयों के बारे में गृह कार्य दिया जाए जिसे विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों की सहायता से पूरा किया जाना था।
- जिले में सरकार से नागरिक संपर्क बिन्दुओं पर 'नो कैश ऑवर्स' शुरू किया गया।
- सक्षम युवा समूहों ने 1,90,000 से अधिक डिजिधन लेने–देन को सरल और सुविधाजनक बनाया
- आंरभ में 1,558 मुख्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया जिन्होंने उसके बाद विभिन्न विभागों के
 8,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया।
- तहसील और उप मंडल स्तर पर व्यापारियों, पेट्रोल पंप मालिकों, आमजन के लिए प्रशिक्षण कैंप लगाए गए। इसके अलावा, रिक्शा चालकों और सब्जी विक्रेताओं को भी प्रशिक्षण दिया गया।
- डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म (जैसे कि फेसबुक और ट्विटर)
 का उपयोग किया गया। डिजिटल भुगतान के बारे में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए एसएमएस अभियान चलाया गया। केबल टीवी चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मो पर वीडियो संदेश प्रसारित किए गए।

Awarded District – Sonipat, Haryana Group– Other States

Exemplary Work Done in District under the Programme

- Identification of stakeholders and establishments was done to identify areas with maximum footfalls.
- Digi Dhan Mela was conducted where 170 stalls were set up and footfall was around 1,50,000 and 112 awards were given.
- To augment the digital infrastructure, identification of gap between availability & requirement of Digi infrastructure was done.
- 1100 medium size banners were put up 1,00,000 handbills were circulated. Additionally, banners were pasted on auto-rickshaws in all towns of the District.
- All Government schools spread the benefits of cashless payment to students during morning prayers. Further, private schools were instructed to give homework about digital payment methods which had to be completed by students with the help of their parents.
- 'No Cash Hours' was introduced at Government to Citizen touch points in the District.
- More than 1,90,000 digital transactions were facilitated by Saksham Yuva groups.
- 1558 key employees were trained initially who, in turn, trained 8000 employees of various departments.
- Training camps of traders, petrol pump owners, general public were held at Tehsil and subdivision level. In addition, training was provided to rickshaw drivers and vegetable vendors.
- Social media platforms (such as Facebook and Twitter) were leveraged for promoting digital payments. Bulk SMS campaign was created to generate awareness about digital payments. Video messages were broadcasted on cable TV channels and social media platforms.

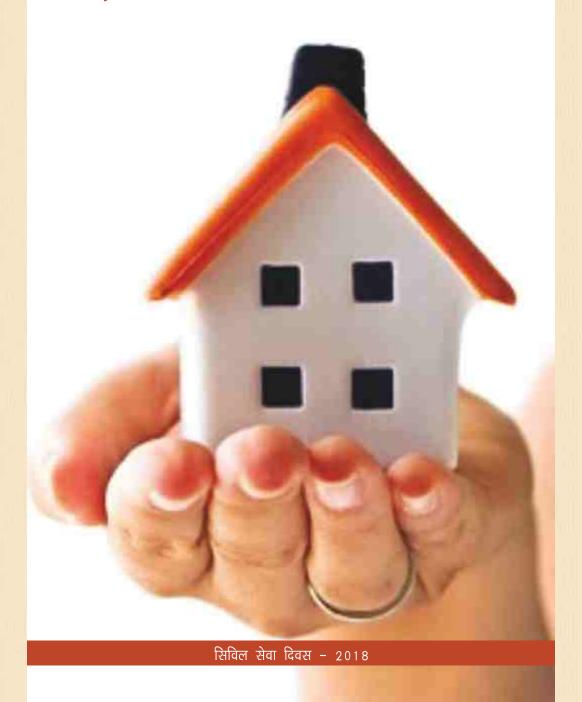
प्रभाव

- सोनीपत 100% नकदीरिहत सब्जी मंडी बनाने में समर्थ हुआ है। इसमें राज्य का पहला 100% नकदीरिहत ई-दिशा केंद्र भी है।
- उचित मूल्य की कुल 366 दुकानों में से 350 दुकानें नकदीरिहत हैं।
- इसके अलावा, सभी 4 उप मंडल, 6 तहसील, 5 नगर निगम कार्यालय नकदीरिहत हैं।
- पीओएस मशीनों की संख्या २७३ (नवम्बर, २०१६) से बढ़ कर ६५८ (नवम्बर २०१७) हो गई हैं।
- इसके अलावा, 81% बैंक खातों में मोबाइल नम्बर दर्ज हैं तथा 82% बैंक खातों में आधार नम्बर दर्ज हैं।
- पिछले 20 महीनों में डिजिटल भुगतान मोड में बिजली बिल भुगतान की प्रतिशतता 4% से बढ़ कर 88% हो गई है।

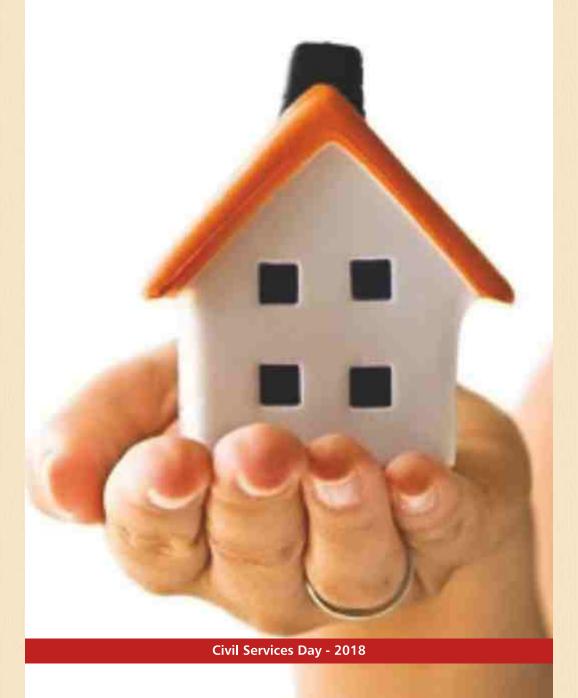
Impact

- Sonipat has implemented 100% cashless enabled Subji Mandi. It also has the state's first 100% cashless e-disha Kendra.
- Out of a total of 366 Fair Price Ration Shops (FPS), 350 are cashless enabled.
- Additionally, all 4 sub divisions, 6 Tehsils, 5 Municipal Offices are cashless enabled.
- Number of POS machine increased from 273 (Nov 2016) to 658 (Nov 2017).
- Further, 81% of Bank accounts were seeded with Mobile and 82% of Bank accounts were seeded with Aadhaar.
- Percentage of Electricity Bill through digital payment mode has increased from 4% to 88% in the last 20 months.

प्रधानमंत्री आवास योजना



Pradhan Mantri Awas Yojana



स्कीम का सार : पीएमएवाई

भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है जिसमें 2022 तक कच्चे और जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे तथा सभी बेघर लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। वास्तव में वंचित लोगों तक सहायता पहुंचाने का लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए पीएमएवाई-जी सामाजिक, आर्थिक तथा जातीय जनगणना (एसईसीसी), 2011 में आवास-अभाव मापदंडों के जिए लाभार्थियों का चयन करता है जो ग्राम सभा द्वारा सत्यापित किया जाना होता है। इस सूचना का उपयोग करते हुए, स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की जाती है तािक, यह सुनिश्चत किया जा सके कि योजना के बेहतर नियोजन तथा कार्यान्वयन के लिए राज्यों के पास इस योजना के तहत कवर होने वाले परिवारों की सुलभ सूची हो। आवास सॉफ्ट और आवास एप्प का उपयोग करते हुए एंड-दू-एंड ई-गवर्नेस मॉडल के जिए कार्यक्रम की मॉनीटरिंग की जाती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा अल्प आय समूहों सिहत शहरी गरीब को वर्ष 2022 तक किफायती आवास उपलब्ध कराना है। यह कार्यक्रम सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को मकान उपलब्ध कराने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जिरए कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करेगा। यह मिशन निम्नलिखित कार्यक्रमों-खंडों के माध्यम से मिलन बस्ती में रहने वालों के साथ-साथ शहरी गरीब की आवासीय जरुरतों को पूरा करने का प्रयास करता है:

- निजी सहभागिता के माध्यम से संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करते हुए मौजूदा मलिन बस्ती में रहने वालों का स्वस्थाने पुनर्वास
- ऋण संबंधी आर्थिक सहायता
- भागीदारी में किफायती आवास
- लाभार्थी-उन्मुख वैयक्तिक गृह निर्माण / विस्तार के लिए आर्थिक सहायता।

Brief of the Scheme: PMAY

Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin is a flagship programme of Government of India with a vision to provide pucca houses, with basic amenities, to all homeless householders and those living in kutcha and dilapidated houses, by 2022. To ensure that assistance is targeted at those who are genuinely deprived, PMAY-G selects beneficiaries using housing deprivation parameters in the Socio Economic and Caste Census (SECC) 2011, which is to be verified by the Gram Sabhas. Using this information, Permanent Wait List is generated to ensure that the States have a ready list of the households to be covered under the scheme leading to better planning and implementation. The monitoring of programme is carried out through an end to end e-governance model using Awaas Soft and Awaas App.

Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban aims to provide affordable housing to urban poor, including Economically Weaker Sections and Low Income Groups in urban areas by the year 2022. The programme will provide central assistance to implementing agencies through States and UTs for providing houses to all eligible families/beneficiaries. The mission seeks to address the housing requirement of urban poor including slum dwellers through the following programme verticals:

- In-situ rehabilitation of existing slum dwellers using land as a resource through private participation
- Credit Linked Subsidy
- Affordable Housing in Partnership
- Subsidy for Beneficiary-led individual house construction/enhancement.

पुरस्कृत जिला – कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश (पीएमएवाई–जी) समूह – पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्य

इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में किया गया अनुकरणीय कार्य

- भूकम्प की दृष्टि से संवेदनशील कांगड़ा जिले के लिए भूकम्परोधी इमारत बनाने हेतु सत्र आयोजित करना।
- निर्माण कार्य से जुड़े सरकारी कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया और स्कीम के दिशा-निर्देशों, निर्माण तकनीक एवं स्कीम के एएमआईएस भाग के विषय में अवगत कराया गया। इस संबंध में स्टेकहोल्डरों को समय-समय पर बताया गया।
- राजिमिस्त्रियों को सरकारी पॉलिटेक्निक सुंदर नगर में ब्लॉक के तकनीकी स्टॉफ को निर्माण तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया।
- मकान निर्माण तथा मॉनीटरिंग के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारियों के मोबाइल पर आवास एप्प डाउनलोड किया गया था।
- मौजूदा तकनीकी विकल्प अर्थात् कर्मचारियों के मोबाइल, ग्राम-स्तरीय अधिकारियों की तकनीकी दक्षता तथा प्रशिक्षित राजिमस्त्री का उपयोग किया गया।
- डिजाइन और वर्गीकरण (टाइपोलॉजी) अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, जिनमें स्थानीय राजिमस्त्रियों के नियोजन तथा स्थानीय डिजाइनों तथा भूकम्परोधी संरचना को समाविष्ट किया गया
- मकानों का निर्माण लाभार्थी की आवश्यकतानुसार, लागत प्रभावी एवं स्थानीय सामग्री का अधिकतम उपयोग करते हुए किया गया। सभी मकानों के निर्माण में स्कीम की मौलिक आवश्यकता अर्थात् रसोईघर तथा स्वच्छ शौचालय के साथ 25 वर्ग मी. क्षेत्र सुनिश्चित किया गया।
- शहरी क्षेत्रों के बढ़ते प्रभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी ऐसे घरों के निर्माण की सहजता को देखते हुए टिकाऊ और ईंट एवं स्लैब घरों को वरीयता दे रहे थे।
- जिस लाभार्थी का मकान निर्माणाधीन (५५६ मामले) है उसे ९५ दिनों की साधारण मजदूरी उपलब्ध करवाते हुए इसका एमजीएनआरईजीए के साथ सिम्मलन किया गया। सिम्मलन पद्धित में एमजीएनआरईजीए के तहत २३२ शौचालयों का निर्माण कराया गया।

प्रभाव

अभी तक स्वीकृत १०६८ मकानों के लक्ष्य की तुलना में ७११ मकान पूरे कर लिए गए हैं।

Awarded District – Kangra, Himachal Pradesh (PMAY-G) Group – North East & Hill States

Exemplary Work Done in District under the Programme

- Conducting sessions for creating earthquake resistant structures for the seismically sensitive Kangra District.
- Officials and non-officials associated with the construction were trained and equipped with the guidelines of the scheme, construction technologies and MIS part of the scheme. Briefing of these stakeholders was done from time to time.
- Masons were provided training of construction techniques at Government Polytechnic Sunder Nagar along with technical staff of Blocks.
- The Awaas app was downloaded on the mobiles of those Officials who were assigned the houses for construction and monitoring.
- The existing technological options were used i.e. mobiles with officials and technical expertise of field level functionaries and trained masons.
- Design and typology were the crucial requirements, which were incorporated by engaging local masons and using local designs and earthquake proof structures.
- Houses were constructed as per the need of the beneficiary, cost effectiveness and maximum use of local materials. The basic requirement of the scheme i.e. 25 sq. mt. area along with kitchen and sanitary latrine was ensured in the construction of all houses.
- Due to spillover effect of urban areas, people in rural areas were opting for brick masonry and slab houses owing to the durability and ease of construction of such houses.
- Convergence was done with the MGNREGA by way of providing 95 DAYS unskilled labor to the beneficiary whose house is under construction (556 cases). 232 Toilets were constructed in convergence mode under MGNREGA.

Impact

So far, Out of 1068 sanctioned houses against the target, 711 houses have been completed.

पुरस्कृत जिला – नीमच, मध्य प्रदेश (पीएमएवाई-जी) समूह – अन्य राज्य

इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में किया गया अनुकरणीय कार्य

- जागरुकता लाने के लिए विभिन्न पहलें जैसे कि आवास दिवस पर मकानों के पूरे होने पर जश्न, डिजिटल बैंकिंग संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन, सरकारी बीमा योजना तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गईं।
- ट्विन-पिट शौचालयों का निर्माण, आवासीय शौचालयों के प्रयोग तथा खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) वातावरण के लाभों के समर्थन में अनेक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभियान चलाए गए।
- इसके अतिरिक्त, जिले ने उएम सरलीकरण ढांचा (मैन, मैसन, मैटिरियल) अपनाया। इसके अलावा, एक पारिवारिक प्रोफाइल (जीवन स्तर, सामाजिक सूचकों और आर्थिक सूचकों के आधार पर) तैयार करते हुए पीएम परिवार कार्ड जारी किया गया तथा ब्यौरा पोर्टल पर अद्यतन किया गया।
- निर्माण, मॉनीटरिंग आदि के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों का क्षमता निर्माण किया गया। जिले ने मैसन्स को 'राजिमस्त्री' के रूप में प्रशिक्षण देने के लिए सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों को समाविष्ट करते हुए ब्लॉक स्तर पर 45 दिनों का प्रशिक्षण प्रदान किया। इस उद्देश्य से 105 साधारण मजदूर, प्रत्येक ब्लॉक से 35, चयनित किए गए तथा राजिमस्त्री के रूप में प्रशिक्षित किए गए। 2016-18 के दौरान कुल 732 लोग साधारण मजदूर से प्रमाणित कुशल 'राजिमस्त्री' बने। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान नमूना मकानों का निर्माण किया गया।
- अधिकारियों को प्रौद्योगिकी माध्यमों (जैसे जियो–टैगिंग तथा सॉफ्टवेयर हैंडलिंग) का प्रयोग करने संबंधी प्रशिक्षण दिया गया।
- केवल स्थानीय रूप से उत्पादित निर्माण सामग्रियों (जैसे स्लैब निर्माण हेतु सिंगोली पत्थर तथा फर्श के लिए सुवखेड़ा पत्थर, ईंट और सीमेंट आदि) के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया।
- जिला प्रशासन ने सामग्रियों तथा निर्माण सामग्रियों की किफायती दर पर खरीद के लिए समय पर राशि का अंतरण सुनिश्चित किया।
- अन्य स्कीमों के साथ सिम्मलन किया गया जिनमें उज्जवला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन, सौभाग्य योजना के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराई गई तथा स्वच्छ भारत अभियान (एसएमबी) के माध्यम से शौचालयों का निर्माण कराया गया। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना के तहत 12 ईंट भट्टे लगाए गए जो निर्माण सामग्री की आपूर्ति करते थे। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना के तहत 46 सेन्ट्रिंग उद्यम लगाए गए जो पीएमएवाई (ग्रामीण) के अंतर्गत मकान निर्माण कार्य करते थे। 150 स्व-सहायता समूह, जिनके सदस्य इस स्कीम के लाभार्थी हैं, को बैंक से जोड़ा गया।

प्रभाव

अब तक, 5026 स्वीकृत मकानों के लक्ष्य की तुलना में 3931 मकान पूरे कर लिए गए हैं।

Awarded District – Neemuch, Madhya Pradesh (PMAY-G) Group – Other States

Exemplary Work Done in District under the Programme

- Several initiatives were undertaken for creating awareness such as celebration of the completion of houses on Awas Diwas, programmes conducted on digital banking, Government insurance schemes and Mukhya Mantri Swarozgar Yojana.
- Multiple hygiene and sanitation drives were conducted in the form of construction of twin-pit toilets, community level meetings to sustain use of household toilets and benefits of Open Defection Free (ODF) environment.
- In addition, 3M Facilitation Model (Man, Mason, Material) was adopted by the District. Further, a PM Parivar card was issued by creating a family profile (based on standard of living, social indicators and economic indicators) and updating details on the portal.
- Capacity building of officers was undertaken at different levels on construction, monitoring, etc. The District provided 45 days training, comprising of both theory and practical, held at Block level to train masons as 'Rajmistris'. For this purpose, 105 unskilled labourers, 35 from each block, were selected and trained as 'Rajmistris'. A total of 732 people were transformed from unskilled labourers into certified skilled 'Rajmistris' during 2016-18. Model houses were constructed during training programmes.
- The officers were trained to use technology mediums (such as geo-tagging and software handling).
- Use of only locally produced construction materials (such as Singoli stone for slab construction and Suvakheda stone for flooring, bricks and cement, etc.) were promoted.
- District Administration ensured timely transfers of funds for purchase of materials and construction materials at affordable rates
- Convergence was done with other schemes by way of gas connections provided through Ujjwala Yojana, electricity connections through Saubhagya Yojana and toilets constructed through Swachh Bharat Mission (SBM). Additionally, 12 brick enterprises were set up under Mukya Mantri Swarozgar Yojana which have supplied construction materials.46 centering enterprises were set up under Mukya Mantri Swarozgar Yojana which have provided services in construction of houses under PMAY (Gramin). 150 Self Help Groups (SHGs), whose members are beneficiaries of the scheme were provided with bank linkages.

Impact

So far, out of 5026 sanctioned houses against the target, 3931 houses have been completed.

पुरस्कृत जिला – पुडुचेरी शहरी स्थानीय निकाय, पुडुचेरी (पीएमएवाई–यू) समूह – केंद्र शासित प्रदेश

इस कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकाय में किया गया अनुकरणीय कार्य

- संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने पीएमएवाई के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने के दृष्टिकोण से प्रिंट और डिजिटल मीडिया के माध्यम से स्कीम की विस्तृत जानकारी दी।
- आवासीय मांग सुनिश्चित करने के लिए सामान्यजन से आवेदन आमंत्रित किए गए। भूमि के स्वामित्व के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर प्राप्त आवेदनों को पृथक किया गया।
- स्थल सत्यापन द्वारा प्रमाणीकरण किया गया जिसमें डुप्लीकेट लाभार्थियों को हटाना शामिल है। पीएमएवाई के शीर्ष बेनेफिशियरी लेड कन्स्ट्रक्शन के अंतर्गत चयन हेतु योग्य पाए गए आवेदनों की सूची प्रमाणीकरण प्रक्रिया के पश्चात विभिन्न कार्यालयों और संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी कार्यालयों में विशिष्ट प्रदर्शन द्वारा सामाजिक जांच के लिए प्रदर्शित किए गए। इसके अतिरिक्त, यह सूची सूचनार्थ सरकारी वेबसाइट पर अपलोड भी की गई।
- जनसामान्य को समाचार पत्र विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया गया और सामान्य जन को लाभार्थियों की सूची के संबंध में अपने विचार/आपत्ति/टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए सीमित समयाविध दी गई। आम जनता से प्राप्त आवेदनों पर विधिवत रूप से विचार किया गया तथा वित्तीय स्वीकृति को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए अंतिम स्वीकृति देने हेतु पीएमएवाई की राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग तथा चयन सिमित के समक्ष चयन के लिए रखा गया।
- पुडुचेरी सरकार ने पेरुंथलीवर कामराजर सेन्टेनरी आवासीय स्कीम (पीकेसीएचएस), राज्य-स्तरीय आवासीय स्कीम को कवर करते हुए बीएलसी पीएमएवाई के प्रत्येक लाभार्थी के लिए 2 लाख रु. की बढ़ोतरी की गई। इसमें से पीएमएवाई के लिए केन्द्र सरकार ने 1.5 लाख रु. प्रदान किया तथा 50,000/- रु. राज्य आवासीय स्कीम के तहत वित्तीय स्वीकृति दी।
- इसके अतिरिक्त, स्वच्छ भारत अभियान, आईएचएचएल तथा स्मार्ट सिटी अभियान जैसी अन्य स्कीमों
 का भी सिम्मलन किया गया।

प्रभाव

प्राप्त कुल मांग 9077 थी। वैध मांगों की संख्या 7865 तथा कुल स्वीकृत मकान (01.04.2016 - 31.12.2017 के बीच) 4236 थे।

Awarded District – Puducherry ULB, Puducherry (PMAY-U) Group – Union Territories

Exemplary Work Done in Urban Local Body under the Programme

- Government of the Union Territory, with a vision to extend the benefits of the PMAY scheme to all the section of society had given wide publicity about the scheme through print and digital media.
- Applications were invited from public to ascertain the housing demand. The applications received were segregated based on the documentary proof submitted in respect of the ownership of land.
- The validation was undertaken by spot verification, including exclusion of duplicate beneficiaries. The list of the applicants who were found to be the eligible for selection under the Beneficiary Led Construction (BLC) vertical of PMAY were published for social scrutiny by displaying prominently in different offices and respective implementation agency offices. In addition the list was also uploaded in the Government web site for information.
- Public was informed through newspaper advertisements and was given a limited time period for submission of their views / objections / comments with regard to the list of beneficiaries. The submission received from public were duly addressed and the final list was placed for selection to the State level monitoring and selection committee of PMAY for facilitating the financial sanction.
- The Puducherry Government, by converging the state level housing scheme of Perunthalivar Kamarajar Centenary Housing Scheme (PKCHS) extended Rs. 2 lakhs to each beneficiary of BLC- PMAY. Out of this, Rs. 1.5 lakhs was provided by Central Government for the PMAY scheme and Rs. 50,000 was given from the financial sanction made under the State Housing Scheme.
- In addition, there was convergence with other schemes like Swachh Bharat Mission IHHL and Smart Cities Mission was also done.

Impact

The total demand received was 9077. The number of validated demand were 7865 and the total houses sanctioned ((between 01.04.2016 – 31.12.2017) were 4236

पुरस्कृत जिला – ग्रेटर हैदराबाद महानगर निगम, हैदराबाद (पीएमएवाई-यू) समूह – अन्य राज्य

इस कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकाय में किया गया अनुकरणीय कार्य

- आवास की मांग पूरी करने के लिए पूर्विनिर्मित कार्यनीति अपनाने के भाग के तौर पर अनेक कदम उठाए गए जैसे क्षेत्र-विशिष्ट मांग आकलन, स्टेकहोल्डरों से परामर्श, घरों के निर्माण के लिए खाली जमीन की पहचान, रूपरेखा तैयार करना, अनुमोदन प्राप्त करना, लागत का आकलन करना तथा अंत में बजटीय प्रावधान सुनिश्चित करना।
- तेलंगाना सरकार ने एक नवीन संकल्पना और फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू किया जिससे निजी क्षेत्रों के समान अन्तर्निहित रखरखाव तंत्र तथा सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचनाओं से युक्त 2 कमरों के बहुमंजिला घर बनाने में समर्थ हुए। इस मॉडल के तहत 3 प्रकार के घरों जी+3 (स्व-स्थाने), एस+5 (स्व-स्थाने एवं रिक्त) और सी+एस+9 (रिक्त) के निर्माण की योजना बनाई गई।
- ग्रेटर हैदराबाद महानगर निगम के शहरी समुदाय विंग (यूसीडब्लयू) एवं एसआरएसीओ, गैर सरकारी संगठन द्वारा परामर्श और जागरुकता कार्यकलाप किए गए।
- यह कार्य शीयर वॉल प्रौद्योगिकी अपना कर किया गया जो दीवार और स्लैब इकाइयों के उत्पादन में अधिक परिशुद्धता और अत्यंत परिष्कृतता से 1-3 दिन में ही उत्पादन चक्र को सक्षम बनाता है।
- पूर्व निर्मित कंक्रीट भवन निर्माण मॉडल का उपयोग किया गया जिससे स्थल पर श्रम और नक्शा कार्य में कमी आई जिसके फलस्वरूप बेहतर उच्च गुणवत्तायुक्त पूर्वनिर्मित कंक्रीट इकाइयों के जिरए निर्माण में भी तेजी से वृद्धि हुई। इसके अलावा, लाभार्थियों के ऑनलाइन डाटा संग्रहित करने तथा जारी निधि का ब्यौरा लेने तथा परियोजना की भू-टैगिंग के प्रयोजनार्थ एमआईएस का उपयोग किया गया।
- अप्रयुक्त भू-संपत्तियों का पुनः अधिग्रहण करने के लिए सरकार के मुख्य सिचव और जिला कलेक्टरों के सिक्रिय समन्वयन सिहत अन्य विभागों से सिम्मलन किया गया।
- इसके अलावा, जवाहर लाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी (जेएनएएफएयू) ने
 2 बेडरुम के घरों के मॉडल की डिजाइन में सहभागिता की।
- इसके अलावा, पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के विनियमों के अनुपालन में राख की ईंटों तथा पीपीसी सीमेंट का उपयोग किया गया।

प्रभाव

कुल वास्तविक मांग 1,19,255 थी। इसके अलावा, वैध मांग की संख्या 1,07,267 है। इसमें से 01.04.2016 से 31.12.2017 तक स्वीकृत मकानों की कुल संख्या 94,108 है।

Awarded District – Greater Hyderabad Municipal Corporation, Hyderabad (PMAY-U) Group – Other States

Exemplary Work Done in Urban Local Body under the Programme

- As part of the pre-construction strategy adopted to meet housing demand, several steps were undertaken such as area specific demand assessment, consultations with stakeholders, identifying free land for development of houses, preparation of layout, obtaining approvals, preparation of cost estimations and finally ensuring budget provisions.
- The Government of Telangana brought in a novel concept and a flagship programme to enable 2BHK vertical development houses with inbuilt maintenance mechanism and social and physical infrastructure provision on par with the private sector. This was termed as the 'Dignity Housing' model. Under this model, 3 types of houses were planned to be constructed, i.e. G+3 (In situ); S+5 (In situ and Vacant) and C+S+9 (Vacant).
- Counseling and awareness were activities undertaken by Urban Community Wing (UCW) of GHMC and SRACO NGO.
- Adoption of Shear wall technology which enabled a production cycle of only 1-3 days because of higher precision and smoother finishes in production of walls and slab units.
- Precast concrete building construction model was also used which allowed reduction of in site labor and form work and in turn, increased the speed of construction with improved durability. Additionally, MIS was used for capturing online data of beneficiaries, details of funds released and geo-tagging of projects.
- Convergence with other Departments to reacquire unutilized land holding including coordination by Chief Secretary to Government and active coordination with District Collectors.
- Further, Jawaharlal Nehru Architecture and Fine Arts University (JNAFAU) was involved for the designs of 2BHK housing model.
- In addition, fly ash bricks and PPC cement was used in compliance with regulations by Ministry of Environment, Government of India.

Impact

The total demand received was 1,19,255. Further, the number of validated demand is 1,07,267. Out of this, the total number of houses sanctioned between 01.04.2016 – 31.12.2017 are 94,108.

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कोशल्य योजना



सिविल सेवा दिवस - 2018

Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana



Civil Services Day - 2018

स्कीम का सार : डीडीयू-जीकेवाई

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 25 सितम्बर, 2014 को अन्त्योदय दिवस के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) की घोषणा की। डीडीयू-जीकेवाई ग्रामीण निर्धन परिवारों की आय में विविधता जोड़ने और ग्रामीण युवाओं के कॅरियर की आकांक्षाओं को पूरा करने के दोहरे उद्देश्यों से कार्य करने वाले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का अंग है।

डीडीयू-जीकेवाई गरीब परिवारों के 15 से 35 वर्ष की आयु के बीच के ग्रामीण युवाओं पर अद्वितीय रूप से केंद्रित है। कौशल भारत अभियान के भाग के रूप में यह सरकार के मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, स्टार्ट-अप इंडिया और स्टेंड-अप इंडिया अभियानों जैसे सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 18 से 34 वर्ष की आयु के बीच देश की युवा जनसंख्या की 180 मिलियन से अधिक या 69% भाग अपने ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इनमें से निर्धन परिवारों के रोजगारविहीन या न्यूनतम रोजगार में लगे युवाओं की संख्या लगभग 55 मिलियन है।

Brief of the Scheme: DDU-GKY

The Ministry of Rural Development (MoRD) announced the Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) Antyodaya Diwas, on 25th September 2014. DDU-GKY is a part of the National Rural Livelihood Mission (NRLM), tasked with the dual objectives of adding diversity to the incomes of rural poor families and cater to the career aspirations of rural youth.

DDU-GKY is uniquely focused on rural youth between the ages of 15 and 35 years from poor families. As a part of the Skill India campaign, it plays an instrumental role in supporting the social and economic programs of the government like the Make In India, Digital India, Smart Cities and Start-Up India, Stand-Up India campaigns. Over 180 million or 69% of the country's youth population between the ages of 18 and 34 years, live in its rural areas. Of these, the bottom of the pyramid youth from poor families with no or marginal employment number about 55 million.

पुरस्कृत जिला – धेमाजी, असम समूह– पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य

इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में किया गया अनुकरणीय कार्य

- पुस्तिकाओं के वितरण, बैनरों और गाँवों व ग्राम पंचायतों में बैठकों के आयोजन के माध्यम से जागरुकता लाई गई।
- सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) के माध्यम से यूथ डाटाबेस सर्वेक्षण भी कराया गया।
 डीडीयू- जीकेवाई के अधिकारियों द्वारा विभिन्न गाँवों और पंचायतों के स्कूल बीच में छोड़ देने वाले पात्र युवाओं की पहचान की गई और उन्हें पंजीकृत किया गया तािक उन्हें प्रशिक्षण केन्द्रों पर भेजने के लिए तैयार किया जा सके।
- सीबीओ और उनकी उप सिमितियों को योजना के बारे में जानकारी दी जाती है और उसके अनुसार वे इस पर अपनी बैठकों में चर्चा करते हैं तािक, वे इस स्कीम से अच्छे परिणाम प्राप्त करें।
- नमामि ब्रह्मपुत्र और धेमाजी हाट के दौरान डीडीयू-जीकेवाई स्टॉल का विशेष उल्लेख किया गया था।
- सीबीओ/एसएचजी/वीओ/सीएलएफ जैसे संगठन सुदृढ़ किए गए और उन्हें प्रशिक्षण केन्द्रों तक पहुँच उपलब्ध कराया गया और उन्हें प्रशिक्षणार्थियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ब्लॉक और जिला स्तर पर पीआईए में नियमित बैठकें आयोजित की गई।
- डीडीयूजीकेवाई स्कीम के विषय में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए एमजीएनआरईजीए से सिम्मलन किया गया।
- उम्मीदवारों के ऑनलाइन पंजीकरण और स्कीम से जुड़ी जानकारी के प्रसारण के लिए स्मार्टफोन के उपयोग के लिए कौशल पंजी के प्रोत्साहन से बहु-स्तरीय प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एसएचजी और वीओ के सदस्यों को अपने क्षेत्रों के उम्मीदवारों से मिलने और उनसे बातचीत करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों तक उनकी पहुंच बनाई गई।
- इसके अतिरिक्त, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण केन्द्रों के दौरों के माध्यम से उम्मीदवारों की काउन्सिलंग की गई।
- लोगों को एकत्र करने से पहले पीआईए के साथ नियमित बैठकें की गई और स्कूल बीच में छोड़ देने वालों की संख्या घटाने के लिए कार्यनीतियां अपनाई गई। समुदाय को स्कूल बीच में छोड़ देने के कारणों और उनका सामना करने के सम्भावित तरीकों के प्रति उन्हें जागरुक किया गया और अभिभावकों को इसके लिए परामर्श दिया गया।
- इस कार्यक्रम की स्थिरता और पुनरावृत्ति उस सकारात्मक प्रभाव से उत्पन्न होती है जो समुदाय के वंचित वर्गों के रूप में धेमाजी में सृजित की गई थी और इससे उन्हें अपने कॅरियर और कौशल विकास का लाभ मिला।

Awarded District – Dhemaji, Assam Group – North East & Hill States

Exemplary Work Done in District under the Programme

- Awareness was created through the circulation of leaflets, banners, and conducting meetings in the village and Gram Panchayat.
- A youth database survey through Community Resource Persons (CRPs) was also conducted. Eligible school dropout youths are identified and registered by DDU-GKY officials from different villages and Panchayats so as to prepare them for sending them to training centers.
- The CBOs and their sub committees are given orientation about the Yojana and accordingly they discuss it in their meetings so as to get good output from the Scheme.
- DDUGKY stall was highlighted during NAMAMI Brahmaputra and Dhemaji Haat.
- Organizations such as CBOs/SHG/VO/CLF were strengthened and were provided access to the training centres and encouraged to interact with the trainees. Regular meetings were conducted in the PIAs at Block and District level.
- There was convergence with MGNREGA to create awareness about the DDUGKY scheme.
- Use of technology was promoted at multiple levels by promotion of Kaushal Panjee for online registration of candidates, and the use of smartphones to relay information relating to the scheme.
- To ensure transparency, SHG and VO members were given access to the training centres to meet candidates from their region and interact with them.
- In addition, the candidates were counseled by District and Block level officials through visits to the training centres.
- Before mobilization, regular meetings were conducted with PIAs and strategies were adopted to reduce the number of dropouts. The community was made aware about the reasons of dropouts and the possible ways to combat them, and the parents are counselled for the same.
- The sustainability and replicability of this programme stemmed from the positive impact that was created in Dhemaji as deprived sections of the community gained access to a career and develop their skills

प्रभाव

- प्रशिक्षण के लिए आवंदित जिले के 1875 उम्मीदवारों के लक्ष्य में से 153 उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण
 पूरा किया। इसके अलावा, और 120 उम्मीदवार 3 या अधिक महीनों के लिए रखे गए।
- जिले के एसईसीसी घरों के उम्मीदवारों से कम से कम एक वंचित उम्मीदवार की संख्या 1,55,978
 है और कुल 272 उम्मीदवार एकत्र किए गए।

Impact

- Out of the allocated District target of 1875 for training, 153 candidates completed training. Further, 120 candidates are placed for 3 or more months.
- The number of candidates in SECC households in the District with at least one deprivation is 1,55,978 and a total of 272 candidates were mobilized.

पुरस्कृत जिला – करीमनगर, तेलंगाना समूह – अन्य राज्य

इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में किया गया अनुकरणीय कार्य

- पंचायत स्तर पर अभियानों और विभिन्न मीडिया माध्यमों से प्रचार के जरिए जागरुकता लाई गई।
- जूनियर कॉलेजों के दौरे किए गए जहाँ युवा बेरोजगारों को कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई तथा रिसोर्स व्यक्तियों ने युवाओं से सम्पर्क किया।
- प्रिक्रया के प्रत्येक स्तर पर समुदाय संगठनों जैसेकि स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और ग्राम संगठनों (वीओ) को विशेष रूप से प्रेरणा और जागरुकता बढ़ाने, कौशल अंतरों की पहचान, लिक्षत कौशलों की पहचान, और छात्रों के पंजीकरण में शामिल किया गया। गैर-सरकारी संगठनों, जनप्रतिनिधियों और कार्यक्रम के पूर्व छात्रों ने उम्मीदवारों को प्रेरित करने में योगदान किया।
- इस कार्यक्रम के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में एसएमएस अलर्ट, वीडियो कॉल सुविधा के माध्यम से नियोक्ताओं से सम्पर्क और रोजगार की भूमिका आधारित काउन्सिलंग वीडियो का प्रयोग शामिल था।
- पंजीकरण, काउन्सलिंग और शिकायतों के निवारण के लिए कॉल सेंटर सहायता भी स्थापित किया
 गया और उम्मीदवारों की सफलता की कथाएं कार्यक्रम की वेबसाइट पर साझा की गईं।
- पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ग्राम स्तर पर स्क्रीनिंग शिविरों के जरिए उम्मीदवारों का चयन किया गया। प्रशिक्षण और नियोजन के सभी विवरण प्रोग्राम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए। उम्मीदवारों/प्रशिक्षणार्थियों की प्रगति रिपोर्टे तैयार की गईं जो प्रशिक्षण केन्द्रों पर अभिभावकों की मासिक बैठकों में उनके साथ साझा की गईं।
- जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण के स्टाफ स्कूल बीच में छोड़ देने वाले युवाओं को एकत्र और उनकी काउंसलिंग करने के लिए उनके घर गया और स्टेकहोल्डरों से फीडबैक लिए।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी), सेक्टर स्किल कौंसिल (एसएससी) या ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने मान्यता दी जिसमें 50% अजा/अजजा, 15% अल्पसंख्यकों, 33% महिलाओं और 3% दिव्यांगजनों के अनिवार्य कवरेज के साथ 90 दिन की न्यूनतम अविध व 75% रोजगार की आश्वासन दिया गया।

Awarded District – Karimnagar, Telangana Group – Other States

Exemplary Work Done in District under the Programme

- Awareness was created through campaigns at Panchayat level and wide publicity through various media mediums.
- Visits to junior colleges were made where the young unemployed were briefed about the programme and resource persons interacted with the youth.
- At every level of the process, community organizations like SHGs and Village Organizations (VOs) were involved at every level of the process, specifically in motivation and awareness generation, identification of skill gaps, identification of target skills, and registration of students. NGOs, public representatives, and alumni of the programme were also involved in motivation of candidates.
- The use of the technology for this programme involved SMS alerts, interaction with employers through video call facility, and counselling with job role based videos.
- Call centre support for registration, counselling, and grievances redressal was also established, and success stories of candidates were shared on the website of the programme.
- To maintain transparency, candidates were selected through screening camps at the village level. All training and placement details were provided on the programmer website. Progress reports of candidates/trainees were prepared which were shared with the parents, supplemented with monthly parent meetings at the training centres.
- District Rural Development Authority staff carried out home visits for mobilization, counselling of dropped out youth and acquired feedback from stakeholders.
- The courses offered in the training programmes were recognized by the National Council for Vocational Training (NCVT), Sector Skill Council (SSC), or Ministry of Rural Development (MoRD), with a minimum duration of 90 days with 75% assured placements, with mandatory coverage of 50% SC/ST, 15% minorities, 33% women and 3% people with disabilities.

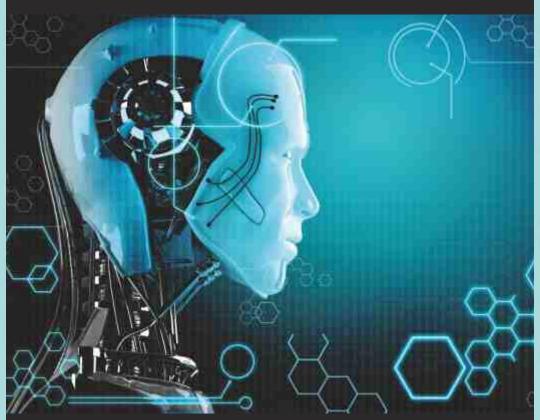
प्रभाव

- 1201 के आवंटित लक्ष्य से अधिक 2209 उम्मीदवार इस कार्यक्रम में प्रशिक्षित किए गए। 2072
 उम्मीदवारों को 3 महीने या अधिक के लिए रोजगार दिए गए।
- जिले में एसईसीसी घरों के कुल उम्मीदवारों के कम-से-कम एक वंचित उम्मीदवार की संख्या
 4,78,473 थी जिनमें से 1% तक कार्यक्रम पहुँचा। जिले में कुल 3767 उम्मीदवार एकत्र किए
 गए।

Impact

- 2209 candidates were trained in the programme, exceeding the allocated target of 1201. 2072 candidates were placed into jobs for 3 months or more.
- The total number of candidates in SECC households in the District with at least one deprivation were 4,78,473, out of which the programme reached to 1%. A total of 3767 candidates were mobilized in the District.

नवाचार



एक बेहतर राष्ट्र, बेहतर विश्व के निर्माण के लिए नवाचार अत्यावश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नवाचार की खोज निरन्तर हो, को बढ़ावा देने वाला वातावरण बनाने और विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा किए जाने वाले असाधारण और नवाचारी कार्य को मान्यता देना आवश्यक है।

सिविल सेवा दिवस - 2018

Innovation



Innovation is imperative to build a better nation, a better world. To ensure that the quest for innovation continues, it is essential to create an encouraging environment and recognize the extraordinary and innovative work done by various Government Organizations.

Civil Services Day - 2018

पुरस्कृत संगठन- जिला प्रशासन, बांका, बिहार

पहल – उन्नयन बांका– प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए शिक्षा में बदलाव– जिला प्रशासन, बांका, बिहार

इस पहल के अंतर्गत जिले में किया गया अनुकरणीय कार्य

- उन्नयन बांका एक मल्टीप्लेटफार्म है जिसमें छात्रों को एलसीडी/एलईडी, टीवी प्रोजेक्टरों, लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसे विभिन्न प्रौद्योगिकीय प्लेटफार्मो पर आधुनिक सक्रिय, प्रसंग के अनुकूल और व्यापक वीडियो मिल रहे हैं।
- मेरा मोबाइल-मेरा विद्यालयः उन्नयन पहल के अन्तर्गत मोबाइल फोन पर किसी भी समय और कहीं
 भी शिक्षण की पहुँच उपलब्ध कराई जा रही है। एप्प में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं:
 - फोकस्ड विषय-वस्तु : 5-10 मिनट का संकल्पना वीडियो (स्कूल में बच्चों को बेहतर तरीके से रोके रखने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा संस्तुत) और स्थानीय भाषा में संदर्भानुकूल विषय-वस्तु।
 - सम्पूर्ण अधिगम चक्रः ऑनलाइन मूल्यांकन, डिजिटल रिपोर्ट कार्ड बनाना, चौबीसों घंटे शंका का निवारण, और वास्तिविक-समय चर्चा समूह उपलब्ध कराए गए। यहां तक कि जिले के सुदूर भाग के छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी भारत और विदेश में फैले आईआईटी स्नातकों, कॉर्पोरेट पेशवरों और शिक्षकों के विशेषज्ञों की टीमों द्वारा दिए जा रहे हैं।
- प्रितयोगिता परीक्षाओं की तैयारी : मोबाइल प्लेटफार्म पर पीओ, एसएससी, आईआईटी, जेईई और संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षाओं के एकीकरण से, छात्र इस प्लेटफार्म पर पाठ्यक्रम विषय-वस्तु का उपयोग करते हुए लाभ उठाने के साथ-साथ मॉक परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं और अपने कार्य-प्रदर्शन पर फीडबैक ले रहे हैं और प्लेटफार्म पर इसी परीक्षा में शामिल होने वाले अन्य छात्रों से अपनी तुलनात्मक रैकिंग भी उन्हें मिल रही है।
- उन्नयन स्मार्ट क्लास में संवादात्मक वीडियो व्याख्यान, कक्षा-मूल्यांकन, श्रव्य शिक्षण आदि सिम्मिलित किए गए हैं। इस स्कीम में स्कूल से बाहर के साथ-साथ स्कूल के माध्यम से बच्चों को सुचारू रूप से शिक्षा उपलब्ध कराने का घटक है। यह एक एलसीडी धारक वैन है जो वामपंथ चरमपंथ प्रभावित सुदूर क्षेत्रों में जाती है और बोर्ड की परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया गहन पाट्यक्रम उपलब्ध कराती है।
- बूट कैम्प शुरू किया गया है जो छात्रों को मोबाइल एप्प डॅव्लॅप्मेंट, वेब डिजाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनेलेटिक्स आदि नवीनतम और अपेक्षित प्रौद्योगिकीय कौशल उपलब्ध कराता है।
- नियुक्तियां सरल बनाने के लिए विशेष नियोजनीयता सेतु कार्यक्रम बनाया गया।

Awarded Organization – District Administration Banka, Bihar

Initiative – Unnayan Banka- Reinventing Education using Technology - District Administration, Banka, Bihar

Exemplary Work Done in District under the Initiative

- Unnayan Banka is a multi-platform model in which students are getting modern day animated, contextualized and comprehensive videos on various technological platforms like LCD/LED TVs, projectors, laptops and mobile phones.
- Mera Mobile-Mera Vidyalaya: Anytime, anywhere learning access is being provided on mobile phones. The app has the following major features:
 - **Focused Content:** 5-10 minutes of concept videos and contextualized content in the local language.
 - **Complete Learning Cycle:** online assessments, digital report cards generation, round the clock doubt solving and real-time discussion groups by students from the remotest part of the District with expert teams scattered throughout India and abroad comprising of IIT graduates, corporate professionals and educators.
- Preparations for Competitive Exams: by integrating PO, SSC, IIT JEE, and UPSC Civil Services on the mobile platform and students benefit by using the course content as well as by appearing in the mock tests on the platform, and getting feedback of their performance and their relative ranking with the other students appearing for the same test on the platform.
- Unnayan Smart Class included interactive video lectures, class assessments, audio learning, etc. School on Wheels is an LCD mounted van that visits LWE affected remote areas and provides specially designed crash course for Board exams.
- Boot camp has been started which provides latest and in demand technological skills to students like mobile app development, web designing, artificial intelligence, big data analytics, etc.
- Special Employability Bridge Programme is in place to facilitate placements.

प्रभाव

- उपस्थिति में 17% से 51% और औसत अंकों में 26% से 77% तक की बढ़ोतरी हुई है।
- मल्टीमीडिया शिक्षण के लिए एलसीडी टीवी का उपयोग करते हुए 5 प्रायोगिक स्कूलों की सफलता के बाद हाईस्कूलों की संख्या 40 स्कूलों तक बढ़ाई गई है।
- भारत भर में 10,000 से भी अधिक शिक्षुओं, शिक्षकों/विशेषज्ञों और अभिभावकों द्वारा ''मेरा मोबाइल– मेरा विद्यालय'' का उपयोग किया जा रहा है।
- 1 7 छात्रों को आईटी क्षेत्र की प्रमुख कम्पनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) में नियुक्ति मिली और उनमें से अधिकतर वंचित वर्गों के हैं।

Impact

- Attendance has increased from 17% to 53% and average marks have increased from 26% to 77%.
- Number of high schools using LCD TVs for multimedia learning have been extended to 40 schools after the success of 5 pilot schools.
- "Mera Mobile-Mera Vidyalaya" is being used by more than 10,000 learners, educators/experts and parents across India.
- 17 students got placement in the IT giant Tata Consultancy Services (TCS) and most of them belong to the underprivileged category.

पुरस्कृत संगठन– टीम जीएसटी, राजस्व विभाग, भारत सरकार, प्रतिनिधित्व – ८ केंद्र तथा ५ राज्य सरकार के अधिकारी

(श्री उपेन्द्र गुप्ता, आयुक्त, सीबीईसी श्री आलोक शुक्ला, संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग श्री अमिताभ कुमार, संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग श्री मनीष कुमार सिन्हा, आयुक्त सीबीईसी श्री जी.डी. लोहानी, ओएसडी, राजस्व विभाग श्री रनवीत खुराना, संयुक्त आयुक्त, सीबीईसी श्री तिखुरार्थ जैन, सहायक आयुक्त, सीबीईसी श्री जगमाल सिंह, उपाध्यक्ष, जीएसटीएन डॉ. पी.डी. वाघेला, कर आयुक्त, गुजरात श्री राजीव जलोटा, वाणिन्यिक कर आयुक्त, महाराष्ट्र श्री ऋत्विक पांडे, सचिव (बजट एवं संसाधन), कर्नाटक श्री अरुण मिश्रा, अपर सचिव, वाणिन्यिक कर, बिहार श्री खालिद अनवर, संयुक्त आयुक्त, वाणिन्यिक कर, पश्चिम बंगाल)

पहल का नाम- जीएसटीः एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार

इस पहल के अंतर्गत किया गया अनुकरणीय कार्य

- 01 जुलाई, 2017 को वस्तु और सेवा कर की शुरुआत करना भारत में अप्रत्यक्ष कर-सुधारों के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम रहा है। जीएसटी की शुरुआत भारतीय उत्पादों को घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी भी बनाएगी। अध्ययन दर्शाते हैं कि इसका आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- जीएसटी में विभिन्न अप्रत्यक्ष कर शामिल कर लिए गए हैं और इस तरह करों की विविधता कम कर दी गई है। जीएसटी के साथ सभी राज्यों में सीजीएसटी/एसजीएसटी/जीएसटी की समान दर लागू है। जीएसटी करों के प्रवाह को रोकता है क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपूर्ति के हर स्तर पर वस्तु और सेवाओं पर उपलब्ध है।
- वस्तु का अन्तिम मूल्य विनिर्माता, खुदरा व्यापारी और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह के कारण कम होने की आशा है।
- जीएसटी में पंजीकरण, रिटर्न, धन-वापसी, कर-भुगतान जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए सरलीकृत
 और स्वचालित कार्यविधियों ने एक पारदर्शी व्यवस्था शुरु की है।
- एनएसीआईएन के नेतृत्व में चार स्तरीय व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु किया गया है। इस प्रशिक्षण परियोजना का उद्देश्य सीबीईसी और राज्य सरकारों के 60,000 से अधिक वाणिज्यिक कर-अधिकारियों को जीएसटी कानून और कार्यविधियों का प्रशिक्षण देना है।
- सीएजी कार्यालय के अधिकारी भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 52,000 से अधिक (राज्यों के लगभग 20,000 अधिकारी) पहले से ही प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। इनमें से 7,000 अधिकारी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भी भाग ले चुके हैं।

Awarded Organization – Team GST, Department of Revenue, Government of India, represented by 8 Central & 5 State Government Officers

(Shri Upender Gupta, Commissioner, CBEC Shri Alok Shukla, Joint Secretary, DoR Shri Amitabh Kumar, JS, DoR Shri Manish Kumar Sinha, Commissioner, CBEC Shri G.D. Lohani, OSD, DoR Shri Ranveet Khurana, Joint Commissioner, CBEC Shri Siddharth Jain, AsstCommissioner, CBEC Shri Jagmal Singh, Vice President, GSTN Dr PD Vaghela, Commissioner Tax, Gujarat Shri Rajiv Jalota, Commissioner Commercial Tax, Maharashtra Shri Ritvik Pandey, Secretary (Budget & Resources), Karnataka Shri Arun Mishra, Additional Secretary, Commercial Tax, Bihar Shri Khalid Anwar, Joint Commissioner, Commercial Tax, West Bengal)

Name of the Initiative - GST : One Nation, One Tax, One Market Exemplary Work Done under the Initiative

- Introduction of Goods and Services Tax on 1st of July 2017 has been a very significant step in the field of indirect tax reforms in India. Introduction of GST would also make Indian products competitive in the domestic and international markets. Studies show that this would have a positive impact on economic growth.
- GST has subsumed various indirect taxes thus the multiplicity of taxes is reduced. With GST, uniform rate of CGST/SGST/IGST is applicable across all states. GST prevents cascading of taxes as Input Tax Credit is available across goods and services at every stage of supply.
- Final price of goods is expected to be lower due to seamless flow of input tax credit between the manufacturer, retailer and supplier of services.
- Simplified and automated procedures for various processes such as registration, returns, refunds, tax payments, etc in GST has introduced a transparent system
- A massive four-tier training programme has been conducted under the leadership of NACIN. This training project is aimed at imparting training on GST law and procedures to more than 60,000 officers of CBEC and Commercial Tax officers of State Governments.
- Officers of the office of CAG are also participating and getting trained in this training programme. More than 52000 officers (including around 20000 officers from States) have already been trained. Out of these 7000 officers have attended refresher training course also.

प्रभाव

- यह निर्यात और विनिर्माण कार्य को बढ़ाएगा, अधिक रोजगार पैदा करेगा और इस तरह पर्याप्त आर्थिक वृद्धि के लिए लाभकारी नियोजन के साथ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि होगीः
- करों की अधिक निष्पक्षता, विशेष रूप से हमारे उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाना और भारतीय निर्यातों को बढावा देनाः
- देश में निवेश के समूचे परिवेश में सुधार जिससे स्वाभाविक रूप से राज्यों को विकास का लाभ होगा।
- अनुवर्ती लागत में कटौती करों की विविधता के लिए अलग–अलग रिकॉर्ड नहीं रखना रिकार्ड की देखरेख में संसाधनों और मानवश्रम का कम निवेश।

Impact

- It will boost export and manufacturing activity, generate more employment and thus increase GDP with gainful employment leading to substantive economic growth.
- More efficient neutralization of taxes especially for exports thereby making our products more competitive in the international market and give boost to Indian Exports.
- Improvement in the overall investment climate in the country which will naturally benefit the development in the states.
- Reduction in compliance costs No multiple record keeping for a variety of taxes- so lesser investment of resources and manpower in maintaining records.

पुरस्कृत अधिकारीगण- टीम इंडिया- प्रतिनिधित्व- श्री शैलेन्द्र सिंह, अपर सचिव और श्री रविन्द्र, संयुक्त सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार

पहल का नाम- व्यवसाय की सुगमता

विश्व बैंक अपने व्यवसाय सुगमता अध्ययन में वार्षिक रूप से 10 पैरामीटरों में 190 देशों की रैंकिंग करता है। ये पैरामीटर हैं:- व्यवसाय शुरु करना, निर्माण संबंधी परिमट प्राप्त करनाः बिजली मिलना, सम्पित्त पंजीकरण, छोटे निवेशकों का संरक्षण, कर भुगतान, सीमा पार व्यापार, संविदाएं लागू करना और दिवालिएपन का समाधान करना। विश्व बैंक ने इन 10 पैरामीटरों की रैंकिंग जानने के लिए भारत के दो शहरों दिल्ली और मुम्बई का मूल्यांकन किया।

इस पहल के अंतर्गत किया गया अनुकरणीय कार्य

- व्यवसाय की सुगमता पहल शुरू करने का उद्देश्य लालफीताशाही खत्म करके निवेशक अनुकूल व्यवसाय माहौल तैयार करने और विनियम ढांचे कारगर बनाकर अनुकूल व्यवसाय माहौल तैयार करना है।
- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल शुरु किया जिसका उद्देश्य सिफारिशों के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वास्तविक समय की रैंकिंग करना और निगरानी करना है तथा अनुभव से अर्जित अच्छी कार्य-प्रणालियाँ सीखने और दोहराए जाने के लिए उपलब्ध कराना है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की 340 बिंदुओं पर कार्यान्वयन की अंतिम रैंकिंग नवम्बर, 2016 को जारी की गई।
- वर्ष 2017 में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने 12 व्यापक पैरामीटरों में 372 सुधारों की पहचान की जिनमें श्रिमक एनेबलर्स, संविदा लागू करना, संपत्ति पंजीकरण, निरीक्षण एनेबलर्स, एकल खिड़की प्रणाली, भूमि उपलब्धता और आवंटन, निर्माण परिमट एनेबलर्स, पर्यावरण पंजीकरण एनेबलर्स, अनिवार्य सेवा परिमट प्राप्त करना, कर चुकाना, सूचना तक पहुंच बनाना और पारदर्शिता तथा कुछ क्षेत्र-विशिष्ट सुधार शामिल हैं।
- अधिकारियों ने चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो सुधारों की पहचान करने और प्रस्तावित सुधारों हेतु कार्य योजना तैयार करने में योगदान किया है।
- उन्होंने राज्य सरकारों के लिए व्यवसाय सुधार कार्य योजना तैयार करने की अपने विपुल अनुभव के जिए योगदान किया।
- उन्होंने किटन और श्रमसाध्य सुधारों के कार्यान्वयन के लिए अथक कार्य किए जिनमें समीक्षा बैठकें करना, स्टेकहोल्डरों से परामर्श, लागू सुधारों पर रिपोर्टे तैयार करना, सुधारों का व्यापक प्रचार करना तथा सुधार के दावों की जमीनी हकीकत जानने के लिए फील्ड दौरा करना शामिल है।
- उनके दृष्टिकोण और दृढ़ स्वभाव ने यह सुनिश्चित करने में सहायता की कि जो सुधार अन्यथा असंभव लग रहा था वह रिकार्ड समय में लागू हो गया।

Awarded Officers – Team India represented by Shri Shailendra Singh, Additional Secretary & Shri Ravinder, Joint Secretary, Department of Industrial Policy & Promotion, Government of India Name of the Initiative – Ease of Doing Business

World Bank, as part of their Doing Business study, ranks 190 countries across 10 parameters annually. These parameters are: Starting a Business, Dealing with Construction Permits, Getting Electricity, Registering Property, Protecting Minority Investors, Paying Taxes, Trading across Borders, Enforcing Contracts and Resolving Insolvency. In India, World Bank assesses two cities, Delhi and Mumbai across these 10 parameters to arrive at country ranking.

Exemplary Work Done under the Initiative

- EoDB initiative has been launched with an aim to create a conducive business environment by streamlining regulatory structures and create an investor-friendly business climate by cutting through red tape.
- An online portal was launched by DIPP with the aim to provide real time ranking and tracking of the States and UTs based on the implementation of the recommendations and details of the good practices to learn and replicate from the experience. Final ranking of State/UTs on implementation of the 340 points were released in November, 2016.
- In 2017, DIPP has identified 372 reforms across 12 broad parameters covering; Labour Enablers, Contract Enforcement, Registering Property, Inspection Enablers, Single Window System, Land Availability and Allotment, Construction Permit Enablers, Environment Registration Enablers, Obtaining Utility Permits, Paying Taxes, Access to Information and Transparency and certain Sector Specific Reforms.
- The officers have contributed in identifying the reforms, whether in Central Government Ministries or State Government and development of an Action Plan for proposed reforms.
- They have contributed through their vast experience in development of Business Reforms Action Plan for State Governments.
- They tirelessly worked towards implementation of difficult and time taking reforms by conducting review meetings, engaging in stakeholder consultation, preparation of reports on reforms implemented, publicising reforms for wider reach and field visits to ground truth claimed reforms.
- Their vision and uncompromising attitude has helped in ensuring that reforms which look otherwise impossible have been implemented in record time.

प्रभाव

- भारत ने विश्व बैंक के व्यापार विनियामक परिवेश के स्वतंत्र आकलन में श्रेष्ठ कार्य-प्रदर्शन किया।
- विश्व बैंक ने इस कार्य में प्रयासों को स्वीकार किया है जिसमें व्यापार सुगमता में भारत का स्थान वर्ष 2014 के 142 से आगे बढ़कर वर्ष 2017 में 100 हो गया है । भारत ने 30 अंकों की छलांग लगाई है जो वर्ष 2017 में किसी देश के लिए सबसे अधिक है।
- पहली बार भारत ने शीर्ष 100 अर्थव्यवस्थाओं में स्थान बनाया और केवल एक वर्ष के भीतर 30 रैंक ऊपर पहुँचा।
- विश्व बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भारत का दौरा किया और प्रवासी भारतीय केंद्र, नई दिल्ली में 4 नवम्बर, 2017 को आयोजित कार्यक्रम में इस प्रकार के दुर्लभ कार्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार को बधाई दी।
- देश भर के राज्य अब अपनी रैंक का उल्लेख करते हैं यदि उन्होंने डीआईपीपी के राज्य रैंक में शीर्ष 10वां स्थान प्राप्त किया हुआ हो। प्रत्येक राज्य अन्य से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है।

Impact

- India marked its best performance on the independent assessment of business regulatory environment by the World Bank.
- World Bank has recognised efforts made in this exercise where India's rank in Doing Business Rankings has gone up from 142 in 2014 to 100 in 2017. India has made a jump of 30 in ranking which is highest jump in ranks by any country in 2017.
- For the 1st time India broke the ceiling of top 100 economies and scaled 30 ranks within just 1 year.
- The CEO of World Bank visited India and congratulated Prime Minister and Indian Government for such rare feat in the programme organized on 4th November, 2017 at Pravasi Bhartiya Kendra, New Delhi.
- The States across country now quote their rank if they are in top 10 in DIPP's state ranking. Every state is making efforts to outdo others.

पुरस्कृत अधिकारीगण- श्री युगल किशोर जोशी, निदेशक, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार

पहल का नाम – स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) – सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए किए गए सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) कार्यकलाप मिशन के अंतर्गत व्यवहारगत बदलावों के लिए संवाद प्रयासों का अभिन्न अंग है। स्वच्छ भारत मिशन का प्रमुख पहलू स्वच्छता संबंधी व्यवहारों में बदलाव करने पर फोकस करना है जो इसे सरकार के पूर्व के स्वच्छता कार्यक्रमों से अलग करता है।

इस पहल के अंतर्गत किया गया अनुकरणीय कार्य

- श्री युगल किशोर जोशी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शुरू किए गए आईईसी (सूचना शिक्षा संचार) कार्यकलापों पर फोकस किया।
- श्री जोशी ने अनेक जन-सामूहिक कार्यक्रमों जैसे कि 'स्वच्छ शक्ति समारोह', स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि, स्वच्छता ही सेवा और स्वच्छ शक्ति, 2017 के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- उन्होंने दरवाजा बंद और शौचा सिंह श्रृंखलाओं जैसे उच्च क्षमता के मीडिया विज्ञापनों की योजना बनाई, जो निरन्तर स्वच्छता व्यवहार अपनाने को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रचारित-प्रसारित की गईं।
- उन्होंने खुले में शौच का बरसों से जुड़ा मिथ तोड़ने के लिए सेल्समेन शौचा सिंह के केन्द्रीय चरित्र, जो सुरिक्षित साफ-सफाई के लिए शिक्षा, जानकारी और जन जागरुकता उत्पन्न करता है, को केन्द्र में रखकर विशेष रेडियो विज्ञापन तैयार किया।
- उन्होंने इन कार्यक्रमों के लिए समर्थन जुटाने, शौचालयों के निर्माण और तेजी लाने के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मेगा कार्यक्रमों और अन्य राष्ट्रीय अभियानों में अग्रणी भूमिका निभाई।
- श्री जोशी ने स्वच्छ भारत िमशन (ग्रामीण) के आईईसी दिशानिर्देशों का प्रारुप बनाने और जारी करने तथा राज्य सरकारों द्वारा निधियों के व्यय की नीति में बदलाव करने में भी अग्रणी भूमिका निभाते हुए अपना योगदान किया। राज्य सरकारों की इन निधियों से राज्यों और जिलों के लिए आईईसी पर व्यय करना अधिक सरल और सुचारु हो गया।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के सात भाषाओं में मास मीडिया राष्ट्रीय अभियान 'दरवाजा बंद' की अभिकल्पना और कार्यान्वयन में भी अहम भूमिका थी जो देश भर में ग्रामीण स्वच्छता चौम्पियनों के शक्ति संचय का प्रकाश स्तंभ बनी।

Awarded Officer – Shri Yugal Kishore Joshi, Director, Ministry of Drinking Water & Sanitation, Government of India Name of the Initiative – Information, Education and Communication (IEC) of Swachh Bharat Mission (Gramin)

Information Education Communication (IEC) activities were undertaken for Swachh Bharat Mission (Gramin), which is an integral part of the behaviour change communication efforts made under the mission. The focus on changing sanitation behaviours is one of the key aspects of the Swachh Bharat Mission that set it apart from previous sanitation programmes.

Exemplary Work Done under the Initiative

- Shri Yugal Kishore Joshi focused on IEC (Information Education Communication) activities undertaken under the Swachh Bharat Mission (Gramin).
- Shri Joshi played a crucial role in the organization of several mass mobilization events such as 'Swachh Shakti Celebration', 'Swachh Sankalp se Swachh Siddhi', 'Swachhata Hi Seva' and 'Swachh Shakti 2017'.
- He planned high powered media campaigns like Darwaza Bandh and Shaucha Singh series that were broadcasted through electronic and print media to promote adoption of sustainable sanitation behaviour.
- For busting myths and age-old traditions related to open defecation, he planned special radio campaign around a central character, salesman Shaucha Singh who educates, informs and creates mass awareness for safe sanitation.
- He has spearheaded iconic national mega events and rolled out other national campaigns to mobilise support, toilets construction and accelerate momentum for the programmes.
- Shri Joshi has also contributed at the policy level by spearheading the drafting and issue of the IEC Guidelines of Swachh Bharat Mission (Gramin) and changes in policy for expenditure of these funds by State governments that made IEC spends much easier and smoother for States and districts.
- He was also instrumental in the design and implementation of the Swachh Bharat Mission (Gramin) mass media national campaign, Darwaza Band, in seven languages, which became a beacon for rallying forces of rural sanitation champions across the country.

प्रभाव

- स्वच्छता, सफाई और खुले में शौच से मुक्ति को लेकर नागरिकों के मध्य व्यावहारात्मक बदलाव देखा गया।
- एक जागरुकता अभियान के दौरान प्राप्त 2.4 करोड़ शपथ, 2.9 करोड़ चित्रकारी, 2.78 करोड़ निबंध और लगभग 4 लाख लघु फिल्में नागरिकों के बीच प्रभाव को दर्शाती है ।
- 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली जिसमें देश के कोने-कोने से नागरिकों, सशस्त्र बलों, दिव्यांगजनों ने स्वेच्छा से विभिन्न कार्यकलापों के जिरए स्वच्छता और सफाई के लिए श्रमदान किया।

Impact

- Behavioural change has noted among citizens towards sanitation, cleanliness and freedom from open defecation.
- 2.4 crores pledges, 2.9 crores paintings, 2.78 crores essays and about 4 lakhs short films received during one awareness campaign is a reflection of the impact generated among citizens.
- During 'Swachhata Hi Seva' campaign, a huge response was received where citizens, including armed forces and divyangs, across the length and breadth of the country volunteered for Shramdaan towards sanitation and cleanliness through various activities.





